



Date: -08/11/2025

To, The Secretary, Listing Department National Stock Exchange of India Ltd. Exchange plaza, BKC, Bandra (E) Mumbai-MH 400051.	To, The Secretary, Corporate Relationship Department BSE Limited P. J. Towers, Dalal Street Mumbai- MH 400001.
--	---

REF :- (ISIN- INE908D01010) SCRIP CODE BSE-531431, NSE Symbol -SHAKTIPUMP

Sub:- Newspaper Publications of Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2025.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith newspaper publication for Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2025 published on today in the Business Standard in Hindi and The Economic Times in English edition.

Kindly take on record the above information for your reference.

Thanking you,

Yours faithfully
For Shakti Pumps (India) Limited

**Ravi Patidar
Company Secretary**

SHAKTI PUMPS (INDIA) LIMITED

शनिवार, 8 नवंबर 2025

कोलकाता, चंडीगढ़, जयपुर,
नई दिल्ली, भोपाल, मुंबई और
लखनऊ से प्रकाशित।

एक नज़र

‘वृद्धि दर 6.8 फीसदी से ज्यादा रहने की उम्मीद’

मुख्य आर्थिक सलाहकार की अनंत नागेश्वरन ने शुक्रवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 6.8 फीसदी से अधिक रह सकती है। उन्होंने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कटौती और आयकर राहत से खपत में आई तेजी से वृद्धि को बल मिलेगा। जनवरी में संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 6.3 से 6.8 फीसदी के बीच रहने का अनुमान लगाया गया था।

स्विगी को 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी

स्विगी ने शुक्रवार को कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल ने पात्र संस्थागत नियोजन समेत अन्य सार्वजनिक या निजी पेशकश के जरिये 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना को हरी झंडी दे दी है। कंपनी अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करते हुए अपने विचक कॉमर्स कारोबार का विस्तार करने के लिए पूंजी जुटा रही है।

ग्रो के आईपीओ को मिले 18 गुना आवेदन

डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म ग्रो की मूल कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स के आईपीओ को करीब 18 गुना आवेदन मिले। कंपनी को करीब 64,000 करोड़ रुपये की बोलियां हासिल हुईं। पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) की श्रेणी में 22 गुना आवेदन मिले जबकि गैर-संस्थागत निवेशक श्रेणी में 14.2 गुना बोलियां मिलीं।

आज का सवाल

क्या आईपीओ मूल्यांकन पर नियामक की चिंता जायज है?
www.bshindi.com पर राय भेजें।
आप अपना जवाब एफएसएस भी कर सकते हैं।
यदि आपका जवाब हां है तो Y और यदि नहीं तो N लिखकर 57007 पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा
क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर विनियमन है जरूरी?
हां 75% नहीं 25%

ICL Fincorp
गोल्ड लोन @ 9%
वार्षिक ब्याज दर
कम ब्याज दर
ज्यादा मूल्य। आसान प्रक्रिया
TOLL-FREE : 1800 31 333 53

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय फिल्मों की धूम

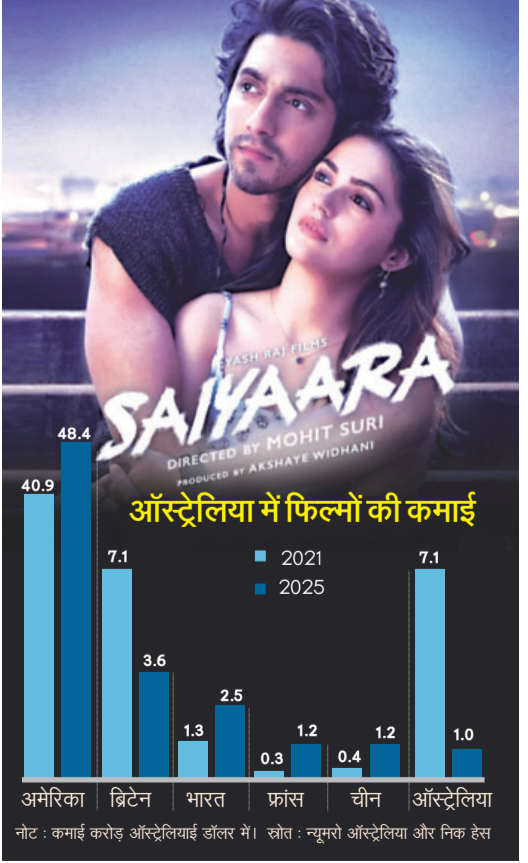
बॉक्स ऑफिस कमाई में ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों को छोड़ा पीछे

वनिता कोहली-खांडेकर
पुणे, 7 नवंबर

भारतीय फिल्मों देश से बाहर भी खूब धूम मचा रही हैं। पिछले 5 वर्षों में ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर भारतीय फिल्मों ने ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों की तुलना में ज्यादा कमाई की है। साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कमाई 1.3 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी 75 करोड़ रुपये थी जो 2025 के अंत तक बढ़कर 2.5 करोड़ डॉलर यानी 143 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है। इस साल अगस्त में ऑस्ट्रेलिया के बॉक्स ऑफिस की कुल करीब 90 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में भारतीय फिल्मों की हिस्सेदारी 4.3 फीसदी से अधिक थी। कमाई के लिहाज से भारतीय फिल्मों के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के बाद ऑस्ट्रेलिया तीसरा सबसे बड़ा विदेशी बाजार है।

सिडनी के फिल्म विश्लेषक निक हेस ने बताया, ‘अंग्रेजी भाषी देशों में से किसी देश में यह पहली बार है जब घरेलू फिल्मों विदेशी भाषा की फिल्मों से पिछड़ गईं। कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में विदेशी भाषा का सिनेमा पहले कभी भी अपने घरेलू भाषा की फिल्मों से आगे नहीं निकला है।’ अक्टूबर के अंत में जारी उनकी रिपोर्ट ‘ऑडियंस स्पिक - इट इज टाइम वी लिसन’ इस बदलते रूझान को उजागर करने वाली पहली रिपोर्ट है।

भारतीय फिल्मों की कुल बॉक्स ऑफिस कमाई का लगभग 38 फीसदी हिंदी भाषा की फिल्मों से आया, जिसमें ‘सैयारा’ और ‘छावा’ इस साल की



नोट : कमाई करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में। स्रोत : न्यूरो ऑस्ट्रेलिया और निक हेस

हिंडाल्को का लाभ 21 फीसदी बढ़ा

डॉलर रु. 88.70 ▲ 10 पैसा | यूरो रु. 102.30 ▲ 30 पैसा | सोना (10 ग्राम) रु. 1,19,619 ▼ 568 रु. | संसेक्स 83216.30 ▼ 94.70 | निफ्टी 25492.30 ▼ 17.40 | निफ्टी फ्यूचर्स 25589.20 ▲ 96.90 | ब्रेंट क्रूड 64.20 ▲ 0.50 डॉलर

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में सुधार और त्योहारी मांग से बिक्री को रफ्तार

वाहन बिक्री में बना कीर्तिमान

शाइन जेकब
चेन्नई, 7 नवंबर

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों के बाद वाहनों की बिक्री ने तेज रफ्तार पकड़ ली। वाहन डीलरों के संगठन फाडा ने शुक्रवार को कहा कि यात्री वाहन की बिक्री अक्टूबर में 5,57,000 के साथ अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई। फाडा ने कहा कि जीएसटी सुधार, त्योहारों पर हुई खरीदारी और ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत मांग से वाहनों की बिक्री को जबरदस्त ताकत मिली है।

दोपहिया वाहनों की बिक्री रिकॉर्ड 31.5 लाख हो गई, जो अक्टूबर 2024 में हुई 21 लाख बिक्री की तुलना में 52 फीसदी अधिक है। अक्टूबर में यात्री वाहन की बिक्री पिछले वर्ष की 5,00,000 की तुलना में 11 फीसदी बढ़ी। इन दो खंडों ने वाहनों की कुल खुदरा बिक्री 40.2 लाख तक पहुंचा दिया। यह अक्टूबर 2024 में हुई 28.7 लाख बिक्री की तुलना में 40.5 फीसदी अधिक है।

पिछले महीने व्यावसायिक वाहनों की बिक्री में 18 फीसदी की वृद्धि हुई। तिपहिया वाहनों की बिक्री 5 फीसदी

वाहन श्रेणी	अक्टूबर 2024	अक्टूबर 2025	वृद्धि
दोपहिया	20,75,578	31,49,846	51.76
तिपहिया	1,22,848	1,29,517	5.43
यात्री वाहन	5,00,578	5,57,373	11.35
ट्रेक्टर	64,416	73,577	14.22
निर्माण उपकरण	8,299	5,769	-30.49
वाणिज्यिक वाहन	91,635	1,07,841	17.69
कुल	28,63,354	40,23,923	40.53

नोट : सालाना वृद्धि फीसदी में। स्रोत: फाडा रिसर्च।

और ट्रेक्टरों की बिक्री 14 फीसदी बढ़ी। फाडा के आंकड़ों में एक अलग श्रेणी निर्माण उपकरण की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में 30 फीसदी कम हो गई। सितंबर में दुर्गा पूजा से शुरू होकर अक्टूबर में छठ पूजा के साथ समाप्त

त्योहारों के दौरान समग्र वाहन बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में 21 फीसदी अधिक थी। फाडा के अध्यक्ष सी एस विन्नेश्वर ने कहा, ‘जीएसटी 2.0 की शुरुआत से व्यापक बदलाव आए। छोटी कारों पर

सेबी ने आईपीओ मूल्यांकन पर चिंता जताई

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वाण्यय ने शुक्रवार को आईपीओ मूल्यांकन और कुछ कॉर्पोरेट व्यवस्थाओं पर चिंता व्यक्त की और छोटे शेयरधारकों की सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा उपायों की मांग की। वाण्यय ने एक्सीलेंस इनोवेलस द्वारा आयोजित गेटकीपर्स ऑफ गवर्नेंस कार्यक्रम में कहा कि ऐसे कई मामले देखे गए हैं जिनमें प्रवर्तक-शेयरधारकों को बेहतर स्वेप आवंटन के लिए बढ़ा-चढ़ाकर मूल्यांकन होता है। यह अलपंश शेयरधारकों के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि सेबी को इस मामले में भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के साथ मिलकर काम करने की जरूरत हो सकती है। आईपीओ मूल्य निर्धारण पर उन्होंने कहा कि सेबी मूल्यांकन में हस्तक्षेप नहीं करता है।

डॉनल्ड ट्रंप पृष्ठ 10

अगले साल भारत की यात्रा संभव: ट्रंप

जीएसटी दरें कम होने से इनकी बिक्री खासी बढ़ गई। खासकर उन लोगों ने खूब खरीदारी की जो कम बजट वाली कार खरीदना चाह रहे थे। उन्होंने कहा, ‘2025 में 42 दिनों की त्योहारी अवधि में सभी श्रेणियों में अब तक की सबसे अधिक बिक्री एवं वृद्धि दर्ज हुई।’ डीलरों के पास पीवी इन्वेंट्री सितंबर के लगभग 60 दिनों से घटकर 53-55 दिनों पर आ गई। मारुति सुजुकी ने अक्टूबर में बिक्री में 18 फीसदी की वृद्धि दर्ज कर 2,39,000 कारों के साथ भारत की शीर्ष कार निर्माता कंपनी के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। टाटा मोटर्स ने 75,352 कारें और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 67,918 कारें बेचीं। ह्यूंडै मोटर इंडिया की बिक्री 7 फीसदी घटकर 65,442 वाहन रह गई। दोपहिया वाहन विनिर्माताओं में हीरो मोटोकोर्प ने अक्टूबर में 9,94,787 वाहन बेचे। होंडा मोटरसाइकल एंड स्कूटर इंडिया की बिक्री 48 फीसदी बढ़कर 8,21,976 वाहन हो गई। टीवीएस मोटर की बिक्री 58 फीसदी बढ़कर 5,58,075 वाहन रही।

विन्नेश्वर ने कहा, ‘ग्रामीण भारत सही मायने में विकास का इंजन बन गया। अनुकूल मौसम, उच्च कृषि आय और सरकारी दृष्टांत प्रोत्साहन से क्रय शक्ति बढ़ रही है।’

‘बोर्ड के निर्णय लेना नियामक का काम नहीं’

अंजलि कुमारी
मुंबई, 7 नवंबर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को कहा कि बैंक के निदेशक मंडलों (बोर्ड) की जगह निर्णय लेना नियामक का काम नहीं है। मल्होत्रा ने कहा कि वित्तीय स्थिरता केंद्रीय बैंक की प्राथमिकता है। उन्होंने अक्टूबर में मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान घोषित सुधारों की घोषणाओं के संदर्भ में यह बात कही।

केंद्रीय बैंक ने पिछले महीने 22 उपायों की घोषणा की थी जिनमें बैंकों को अधिग्रहणों के लिए ऋण देने की अनुमति, शेयर के एवज में ऋण की सीमा बढ़ाने और ऋण हानि की प्रोविजनिंग के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) ढांचे में परिवर्तन के लिए मसौदा मानदंडों को निर्धारित करना शामिल है।

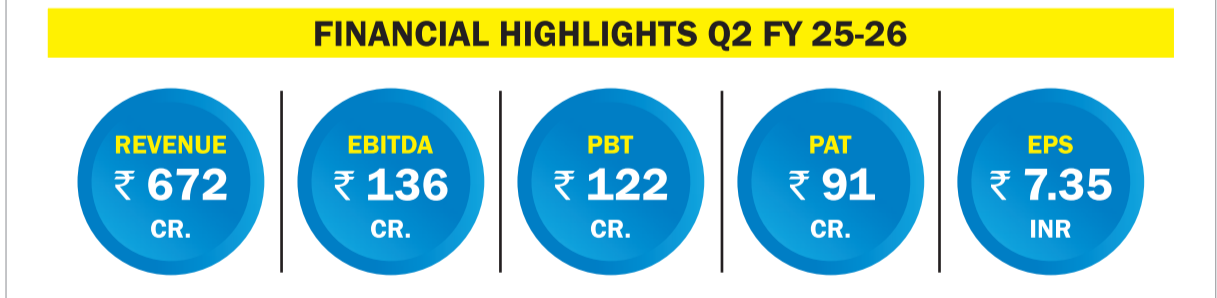


नियामक बैंकों के बोर्ड की जगह फैसले नहीं ले सकता और न ही लेना चाहिए। वित्तीय स्थिरता केंद्रीय बैंक की प्राथमिकता है।

संजय मल्होत्रा
गवर्नर, आरबीआई

पिछले एक दशक में भारतीय बैंकों की वित्तीय सेहत में सुधार हुआ है और उन्हें व्यवसाय करने की अधिक स्वतंत्रता भी मिली है। एसबीआई बैंकिंग एंड इकनॉमिक्स कॉन्फ्लेक्स में मल्होत्रा ने कहा, ‘कोई भी नियामक बैंकों के बोर्ड की जगह फैसले नहीं ले सकता और न ही लेना चाहिए, खासकर भारत जैसे विविधता वाले देश में। प्रत्येक मामला, प्रत्येक ऋण, प्रत्येक जमा, प्रत्येक लेनदेन अलग-अलग जोखिमों और अवसरों के साथ अलग होता है।’

SHAKTI PUMPING LIFE
JAI JAWAN, JAI KISAN
BHARAT KI SHAKTI KO PRANAM
ORDER BOOK
INR 1300* CR



STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED 30th September 2025

S.No	Particulars	Consolidated						Standalone					
		Quarter Ended		Half Year ended		Year ended	Quarter Ended		Half Year ended		Year ended		
		September 30, 2025	June 30, 2025	September 30, 2024	September 30, 2025	September 30, 2024	March 31, 2025	September 30, 2025	June 30, 2025	September 30, 2024	September 30, 2025	September 30, 2025	March 31, 2025
1	Total Income	671.89	624.40	640.32	1,296.29	1,210.84	2,533.33	661.72	612.70	631.83	1,274.42	1,192.14	2,505.04
2	Profit before tax	121.52	129.66	138.45	251.18	264.03	555.80	118.23	125.45	126.33	243.68	247.83	529.39
3	Net Profit for the period after tax	90.71	96.83	101.42	187.54	194.08	408.37	90.20	94.41	94.11	184.61	184.60	393.63
4	Total Comprehensive Income for the period	91.62	97.18	101.22	188.80	194.06	410.67	90.36	94.49	93.54	184.85	184.08	393.43
5	Equity share capital (Face Value: Rs.10/- per share)	123.40	120.21	20.04	123.40	20.04	120.21	123.40	120.21	20.04	123.40	20.04	120.21
6	Earnings per equity share (EPS) of Rs.10/- each	7.35	8.05	8.44	15.40	16.14	33.97	7.31	7.85	7.83	15.16	15.36	32.75
(1) Basic		7.35	8.05	8.44	15.40	16.14	33.97	7.31	7.85	7.83	15.16	15.36	32.75
(2) Diluted		7.34	8.05	8.44	15.39	16.14	33.97	7.30	7.85	7.83	15.15	15.36	32.74

• The Extract of the detailed format of Quarterly Financial Results Filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on Stock Exchanges website: (BSE: <https://www.bseindia.com/>) and NSE: <https://www.nseindia.com/>) and the website of the company <https://www.shaktipumps.com/> which can also be access by scanning QR code.

• The Company operates its business through operating segments, representing our business on the basis of geographies which are India & Overseas.

• The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on November 07, 2025.

• Figures for the corresponding previous periods have been regrouped/rearranged, wherever necessary.

* As on 07th November 2025

Place : Indore
Date: 07.11.2025

For: Shakti Pumps (India) Limited
SD/-
Dinesh Patidar
Chairman & Whole Time Director
(DIN: 00549552)

देश का पम्प शक्ति सोलर पम्प
SHAKTI PUMPS (INDIA) LIMITED

CIN : L29120MP1995PLC009327 | Web: www.shaktipumps.com | E-mail: info@shaktipumps.com, sales@shaktipumps.com
Corporate Office : Plot No. C-04, Silver Spring, Phase-2, Business Park, By-Pass Road, Opp D Mart, Indore-452020, (M.P.) INDIA. Tel.: +91 731 3635000
Regd. Office / Factory Add. : Plot No. 401, 402 & 413, Industrial Area, Sector - 3, Pithampur-454774, Dist. Dhar (M.P.) INDIA. Tel.: +91 7292 410500

FENCE HOSPITALS, SCHOOLS, COLLEGES TO KEEP STRAY DOGS AWAY: APEX COURT TO STATES, UT:

Remove Stray Animals from Public Places & Highways: Supreme Court

Our Political Bureau

New Delhi: The Supreme Court has directed state governments and the National Highways Authority of India (NHAI) to remove stray animals, including cattle, from highways and expressways and to immediately provide shelters and to immediately provide shelters for their rehabilitation. It has also ordered that educational and health institutions be fenced to keep stray dogs away.

A three-member bench headed by Justice Krishna Nath reaffirmed the directions issued by the Rajasthan HC in August for removal of stray animals from roads. On Friday, the SC extended the high court's order to all states and Union Territories. The bench said it has instructed that the directions issued by the Rajasthan HC vide its August order are "affirmed to the extent that public works department, municipal authorities, road and transport authorities to remove cattle from highways and expressways and immediately rehabilitate them in shelters. The top court said "each authority shall constitute a dedicated highway patrol team to report stray cattle on highways and other expressways. All national highways shall have helpline numbers to report presence of stray animals. Chief secretaries of all states shall ensure strict enforcement of these directions".

The SC also directed that governmental as well as private educational and health institutions should be fenced to keep the menace of stray dogs. Such institutions requiring fencing should be identified by the states within two weeks, the bench ordered.

TO PROTECT INDIAN MONKEY FROM 'ILLEGAL CAPTURE, TRADE & CRUELTY'

Environment Ministry Restores Special Protection Level to Rhesus Macaque



Anubhuti Vishnoi

New Delhi: It is a split down the middle with six state governments supporting the move, other states and a Union Territory voting against it while two are neutral and others have not found time to respond to the question whether the Rhesus Macaque or the Indian monkey should be given back special protection under wildlife laws or stay relegated to a lower rung safety net given the high human-monkey conflict.

But the National Board of Wildlife (NBWL) Standing Committee, in its October 20 meeting, affirmed the question, ruling that statutory Schedule II protection should be restored to the species to protect it from "illegal capture, trade and cruelty". After looking at the issue, following representations and views from states, it has been assessed that bringing the Rhesus Macaque under Schedule II would offer greater "administrative

flexibility" for implementing management intervention and conservation actions at state and local level. Chairman of NBWL, panel and environment minister Bhupendra Yadav has called for site-specific management and conservation plans for the Indian monkey along with strengthening of rescue and rehabilitation centres to handle conflict situations and facilitate care for the injured/ displaced. It was also agreed that a baseline study be conducted across states and scientific management measures be brought in with WIJ guidelines, best de-establishment of rescue centres.

Chairman of NBWL, panel and environment minister Bhupendra Yadav has called for site-specific management and conservation plans for the Indian monkey along with strengthening of rescue and rehabilitation centres to handle conflict situations and facilitate care for the injured/ displaced. It was also agreed that a baseline study be conducted across states and scientific management measures be brought in with WIJ guidelines, best de-establishment of rescue centres.

Stripped off the Schedule II protection status under the Wildlife Protection Act, 1972, after 2022 amendments, the Rhesus Macaque was moved down to the lower order Schedule IV species list. While Schedule II status guaranteed more stringent protection to the primate making it illegal to hunt or trade the animals, once delisted and brought to Schedule IV status, any case of cruelty against the animal was subject to prosecution under the less strict Prevention of Cruelty Act. The weakened legal safeguards were strongly opposed by animal rights activists as well as other animal welfare organisations.

Opinions were sought from all states and six states have advocated reinstatement of protection to the Indian monkey, namely Madhya Pradesh, Gujarat, Uttarakhand, West Bengal, Arunachal Pradesh and even Himachal Pradesh which has faced "significant human-Rhesus Macaque conflict". Seven states, including Assam, Rajasthan, Meghalaya, UP, Punjab, Andhra Pradesh and the UT of J&K have opposed it. Tamil Nadu and Nagaland were neutral to it while remaining states are yet to come up with a view.

The monkey question, in fact, has led to another human-wildlife conflict concern involving the leopard. Taking note of the situation, Bhupendra Yadav has directed that all states identify and categorise areas with human-leopard conflicts and submit management proposals in consultations with the Wildlife Institute of India.

OTHER NEWS OF THE DAY

HC's Split Verdict on Rashid's Plea

New Delhi: The Delhi HC on Friday delivered a split verdict on a plea by Kashmir MP Abdul Rashid Sheikh against costs to be paid for shielding Parliament while being in custody, with one of the judges saying he does not have any entitlement and the other holding him liable to pay only reasonable costs towards transportation and not charging him. While Justice Vivek Chaudhary rejected Rashid's plea seeking modification of an order asking him to deposit approximately Rs 4 lakh with jail authorities, Justice Anup Jaaram Bhambhani allowed it. The division bench referred the matter to Chief Justice for appropriate orders. - PTI

NIA Charges One More in Hut Case

New Delhi: The NIA has charged one more accused and filed additional charges against five others in a 2023 Madhya Pradesh terror conspiracy case linked with the proscribed Hizbul Tahrir (HT) terror organisation, NIA said on Friday. The anti-terror agency has filed its first supplementary charge sheet in the case before the NIA special court at Bhopal. With this, a total of 18 accused have so far been charged in the HT conspiracy case. The original charge sheet was filed against 17 accused on November 4, 2023. It added. The supplementary charge sheet filed today has named Mohan Khan alias Dawood, Mohammad Alam, Mirza-ul-Haq, Yaqub Khan, Syed Danish Ali and Mohammad Shaukhat for their involvement in a terrorist act involving the burning of police officer's car on the directives of their foreign handler. - OCB

DELIVERIES TO START IN ABOUT THREE YEARS

HAL Seals Mega Deal with GE for IJ3 Tejas Fighter Jet Engines

Manu Pabby

New Delhi: India has signed a billion-dollar deal with US manufacturer General Electric for new engines that will power the indigenous Tejas fighter aircraft. The deal for IJ3 engines was inked on Friday, with deliveries to start in about three years when the next batch of the aircraft starts getting manufactured. The deal had been in the works for several months as aircraft manufacturer Hindustan Aeronautics Limited (HAL) needed continuity given that it needs to manufacture a total of 300 Light Combat Aircraft (LCA Mk3a) for the air force.

The F 404-EN30 engines are being delivered directly by the US manufacturer. This is separate from negotiations between HAL and GE for a larger deal to manufacture F 404 engines under a technology transfer agreement for next generation LCA Mk2 fighters. The complex agreement that promises over 80% transfer of technology is valued at over \$1.5 billion. In August 2023, HAL inked a deal for 99 of the

F 404-EN30 engines for the first batch of LCA Mk3a. Deliveries under the \$730 million engine deal have commenced, though there's a significant delay in timelines due to supply chain issues faced by GE.

Indian manufacturer HAL says that the engine supply issues have now been resolved, and it is on its way to receive two engines a month, which will be adequate to maintain production lines to produce 24 aircraft on an annual basis.

In September, the defence ministry signed a \$62.75 billion contract with HAL for the procurement of 81 additional LCA fighters. The deliveries of the aircraft are scheduled to commence during 2027-28 and be completed over a period of six years. The latest version of the fighter jets will be manufactured at two production lines in Bengaluru and a third one at Nashik. The plan is to ramp up production capacity to deliver 24 jets on an annual basis in the coming years. The next version of the jet - the LCA Mk2 - is already under prototype production and will be powered by the GE 404 engine which will also be produced in India under the technology transfer deal.



File Arrears Affidavit on MGNREGA: Cal HC to Centre

Our Political Bureau

Kolkata: The Calcutta High Court on Friday directed the Centre to file an affidavit on "the arrears" of the 100-day job scheme under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA). However, the court has observed that the Additional Solicitor General has admitted that "there is some impediment in implementing" the scheme. The Calcutta High Court's division bench

comprising acting Chief Justice Sujay Paul and Justice Parth Sarathi then asked the Centre to file an affidavit on "the benefit of arrears" of the scheme and observed that "we deem it appropriate to grant four weeks to the officials responsible to file their affidavits in opposition."

The Centre had alleged that the funds for the scheme were stopped following massive corruption in the implementation of the scheme. In June, 2023, the Calcutta HC directed the Centre to make payments for the pending MGNREGA funds for West Bengal, acting on a petition filed by Paschimbarngi Khat Majur Samiti, an association of agricultural workers in the state. Additional Solicitor General fairly submits that there is an impediment in implementing MGNREGA in prospective effect," the court observed. The HC noted that the matter will be listed after six weeks.

The 100-day job scheme has approximately 100 million beneficiaries for nearly three years in Bihar, and the Trinamool government has continuously alleged that the Centre "withheld" funds, which has affected poor people. Khat Majur Samiti is the petitioner in this case. While submitting the affidavit on the Union government's behalf in another two weeks from the date of filing of the affidavit by the Centre, a division bench of the HC had dismissed the petition of the HC government in withholding the MGNREGA benefits.

PEACE TALKS IN TURKEY

Pak-Taliban Mistrust Deepens

Dipankar Roy Chaudhury

New Delhi: The current round of Afghanistan and Pakistan peace talks, being held in Istanbul but a second round without a long-term deal. This necessitated a third round. But, according to experts on Afghan affairs, this are expected to remain tense and lukewarm as an aid Pakistan's aggressive policies against Kabul.

as both sides launched a fresh round of peace talks. Both sides signed a ceasefire in Doha on October 19, but a second round of negotiations in Istanbul last week ended without a long-term deal. This necessitated a third round. But, according to experts on Afghan affairs, this are expected to remain tense and lukewarm as an aid Pakistan's aggressive policies against Kabul.

LAND DEAL CANCELLED TO BEST OF MY KNOWLEDGE, SAYS DEPUTY CM

Opposition Slams Maha Govt for Not Naming Parth Pawar in FIR

Krishna Kumar

Mumbai: A day after a land deal involving a company owned by Parth Pawar, Deputy CM Ajit Pawar on Friday claimed that the ₹300 crore deal has been cancelled and a committee has been formed to probe the case. "Not a single rupee was exchanged during the land transaction," Ajit added. Speaking to reporters, he said, "To the best of my knowledge, this land deal is cancelled. An inquiry committee has been appointed to conduct a complete investigation."

The entire saga will be probed to ascertain who all were involved, who helped, who made calls," Ajit claimed that he had nothing to do with the land deal. The Maharashtra government came under attack from the Opposition for a "cover up" in the case after a second FIR was filed involving 11 acres of government land in Pune's Bopodi locality belonging to the state's agricultural department which was transferred to Digvijay Patil, who is the

director of Anandea Enterprises LLP. The Opposition questioned why the FIR did not name Parth even though he owns the majority stake in Anandea Enterprises. Parth has 99% stake in the company even though another of Ajit Pawar's relatives has been booked in the case. Digvijay Patil is the nephew of Suresh Pawar, Ajit's wife. While he holds 1% stake, "We have registered a case against the landowner and eight others for criminal conspiracy cheating and forgery. The landowner is the number two accused. We have arrested three people in the case."

Jarange Accuses Munde of Plotting to Kill Him; NCP Leader Refutes Charge

Krishna Kumar

Mumbai: Marathi quota activist Manoj Jarange Patil on Friday claimed that former Maharashtra minister Dhananjay Munde had planned to kill him and had given a "voucher" of ₹2.5 crore for the same. "Dhananjay Munde initially wanted to defame me with false recordings but since they could not do it so they planned to eliminate me either by giving me some medicines or by running me down in a vehicle. There were 15 to 18 people who were involved in this... We have complained to the police and two people have been arrested in the case."

Matua Community Torn Between Citizenship Hope and SIR Voter List Fears

Jayatri Nag

Kolkata: Amid the special intensive revision (SIR) of electoral rolls in Bengal, the leadership of the Trinamool Congress and the BJP are fighting over the Matua vote bank. The Matua community in Nadia, North 24 Parganas, including Bangaon-considered the hub of the community-and some other districts in the state are apprehensive about SIR, as lakhs of people are still waiting for their citizenship certification under the Citizenship Act/CAA. On Tuesday at an anti-SIR rally where a substantial number of Matuas were present, Trinamool chief and West Bengal chief minister Mamata Banerjee urged the community to stay away from the BJP-run CAA camps and not register their names. Trinamool general secretary Abhishek Banerjee said, "CAA camps in West Bengal do not get trapped. Once you go to these camps and get your name

enrolled, you will meet the same fate as 12 lakh Hindus in Assam. All of you will be sent to detention camps." On the other hand, leader of Opposition Soumitra Adhikari, at a recent rally in the Matua belt, assured the community that not a single name would be deleted and the Matua community should apply for citizenship as CAA has been promised and guaranteed by Prime Minister Narendra Modi. The Matuas, known to be a vote bank of the BJP, have been queuing in large numbers at the CAA camps across the state over the last few months, applying for citizenship and participating in hearings. The Matuas in Bengal are estimated at more than 2 crore in number and over a lakh among them have applied for citizenship. The CAA camps in the Matua belts are being held in North and South 24 Parganas, Nadia and all other border districts by the BJP. The All India Matua Mahasabha general secretary Maheshwari said ET, "We want to give a clear message to the Matuas that they should apply for CAA certificates, as that will be their citizenship proof. We urge the central government to expedite the CAA certificate disbursal process to allay the fears of the community which has come to India after persecution in Bangladesh," Banerjee said. BJP Matua legislator Asim Sarkar is likely to move court next week for the Matua over SIR. Y will be moving.

to court within a week. The EC has to honour the two provisions during the hearing of people who apply for emigration forms after applying for citizenship under the CAA," Sarkar said. "The EC has to honour the MHA number they got immediately after the applications for CAA are accepted." For CAA and Matua move, Trinamool parliamentarian Mamata Bala Thakur-also a Matua Thakurbari member-has started an indefinite hunger strike against SIR. Thakurbari is considered as the Matua community's spiritual and political nerve centre. "We will continue this hunger strike until Centre changes the SIR rules and stops removing names of the refugees from electoral rolls," said Pramadha Banjan Biswas, president of the TMC-backed faction. "Let the Matua apply under CAA. We will urge the EC not to delete names of those missing from the 2002 voter list," Matua Mahasabha chief and Union minister Sitaram Thakur said.

JAI JAWAN, JAI KISAN

BHARAT KI SHAKTI, SHAKTI KO PRANAM

ORDER BOOK INR 1300^{CR}

FINANCIAL HIGHLIGHTS Q2 FY 25-26

REVENUE
₹ 672
CR.

EBITDA
₹ 136
CR.

PBT
₹ 122
CR.

PAT
₹ 91
CR.

EPS
₹ 7.35
INR

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED 30th September 2025 (Rs. in Crores, unless otherwise stated)

Life	Particulars	Consolidated						Standalone					
		Quarter Ended		Half Year ended		Year ended		Quarter Ended		Half Year ended		Year ended	
		September 30, 2025	Jun 30, 2025	September 30, 2024	September 30, 2024	September 30, 2024	March 31, 2025	September 30, 2025	Jun 30, 2025	September 30, 2024	September 30, 2024	September 30, 2024	March 31, 2025
1	Total Income	672.00	624.40	640.22	1,294.27	1,239.99	1,203.22	661.73	622.70	621.42	1,274.42	1,202.14	1,208.84
2	Profit before tax	120.22	128.08	128.46	252.18	254.20	255.88	126.23	125.45	126.23	242.08	242.02	242.26
3	Net Profit to the shareholders	98.71	98.00	98.42	197.34	194.08	194.28	98.28	98.18	98.11	194.08	194.02	194.43
4	Size Compensation to Employees	81.02	87.20	107.22	389.00	394.00	429.07	88.28	94.40	92.94	394.00	394.00	392.42
5	Depreciation	122.48	125.21	125.00	224.40	224.00	225.21	122.48	125.21	125.00	224.40	224.00	225.21
6	Share Issue Costs (₹ in Lakhs)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dividend	1.28	1.28	1.28	2.56	2.56	2.56	1.28	1.28	1.28	2.56	2.56	2.56
8	Dividend	1.28	1.28	1.28	2.56	2.56	2.56	1.28	1.28	1.28	2.56	2.56	2.56

• The Extract of the Audited Financial Results Filed with Stock Exchanges under Regulation 23 of 2023 (Listing Regulations) and Disclosure Requirements (Regulations), and the full form of the Quarterly Financial Results are available on Stock Exchange website: (BSE: <https://www.bseindia.com>) and NSE: (<https://www.nseindia.com>)) and the website of the company: <https://www.shaktipumps.com/> which can also be accessed by scanning QR code.

• The Company operates its business through operating segments, representing its business on the basis of geographical areas as India & Overseas.

• The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on November 07, 2025.

• Figures for the corresponding previous periods have been re-presented/re-recognized, wherever necessary.

* As on 07th November 2025

Place : Indore
Date: 07.11.2025

For: Shakti Pumps (India) Limited
 90-
 Dinesh Patidar
 Chairman & Whole Time Director
 (DIN: 00549552)